प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 35 | मूल्य 15 रुपये | 19-25 जनवरी, 2025

निकाय चुनाव के रंग में रंगा उत्तराखंड, भाजपा-कांग्रेस ने झोंकी ताकत

दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त रेवड़ियों की बहार

वर्ष 14 | अंक 35

दिव्य हिमगिरि

19-25 जनवरी, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

युद्ध विराम पर सहमति से राहत की उम्मीद

इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति की घोषणा निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब तक यह वास्तव में जमीन पर नहीं उतरेगी, तब तक फिर से जंग की आशंका बनी रहेगी। दरअसल, पिछले वर्ष मई के बाद कई बार तात्कालिक या अस्थायी युद्ध विराम को लेकर पहलकदमी हुई, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हमलों में लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहीं। जाहिर है, यह कुछ दिनों के लिए भी युद्ध को विराम देने को लेकर प्रतिबद्धता में कमी और शांति के प्रति उपेक्षा का भाव ही रहा कि अब तक इजराइली हमलों में फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। मगर अब युद्ध विराम के सवाल पर इजराइल और हमास के बीच ताजा सहमति की खबर से इस बार शांति की राह तैयार होने की उम्मीद पैदा हुई है। फिलहाल समझौते का जो स्वरूप सामने आया है, उसके मुताबिक हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से इजराइली बंधकों और इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, गाजा में विस्थापित लोगों को वापस लौटने की भी अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, युद्ध से प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि मौजूदा युद्ध की शुरूआत सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के उस हमले से हुई थी, जिसमें करीब बारह सौ लोग मारे गए थे। उसके बाद हमास को जवाब देने के नाम पर इजराइल के गाजा पर हमले को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना गया था। मगर तब से लेकर पंद्रह महीने बीत चुके हैं और गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक, इजराइल के हमले में अब तक करीब पचास हजार लोग मारे गए हैं। गाजा में बीस लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वह हमास के आतंक का खात्मा कर देगा। लेकिन यह पड़ताल का मसला है कि इजराइल के हमले में हमास के कितने सदस्य मारे गए और कितने आम लोगों को जान गंवानी पड़ी। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में मारे गए आम लोगों में बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। गाजा पर हमले के क्रम में अस्पताल, स्कूल और हमले से बचने के लिए पनाह लेने वाली जगहों को भी नहीं बख्शा गया। युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम-कायदों का भी कोई खयाल रखना जरूरी नहीं समझा गया। इस सबके लिए इजराइल पर जनसंहार और वहां के प्रधानमंत्री पर युद्ध अपराध का आरोप भी लगाया गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई स्तर पर कोशिशें जारी थीं, मगर उसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पा रहा था। अब इतने लंबे समय के बाद अगर युद्धविराम पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकी है तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि अब उसमें कोई अड़चन न खड़ी की जाए, उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाए और शांति निरंतरता में कायम हो। ऐसी स्थिति फिर नहीं पैदा होनी चाहिए कि एक ओर युद्ध विराम पर सहमति की घोषणा हो और दूसरी ओर हमले और उसमें लोगों का मारा जाना जारी रहे। यह एक स्थापित हकीकत है कि किसी भी समस्या या विवाद का हल अंतहीन युद्ध नहीं हो सकता। संभव है कि इस युद्धविराम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट पूरी तरह खत्म न हो, मगर कितने भी जटिल मसले का हल आखिर संवाद के रास्ते से ही गुजरता है।

कुँवर राज अस्थाना

दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त रेवड़ियों की बहार

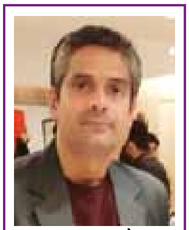

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

देश में कोई त्योहार पर जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां और मॉल ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर करती हैं उसी तर्ज पर देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस वोटरों को आकर्षित करने के लिए कई बड़ी फ्री योजनाओं की सौगात देने का वादा किया है। तीनों पार्टियों ने जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता के लिए एक से बढ़कर एक सौगातों की झड़ी लगा दी है। वैसे यह भी सही है, राजधानी में लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार में फी योजनाओं का लाभ लेने की आदत भी पड़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने इस बार चुनाव में मुफ्त और लोकलुभावन योजनाओं को प्राथमिकता दी है।

देश में कोई त्योहार (फेस्टिवल) जैसे होली, दीपावली, 26 जनवरी, और 15 अगस्त जैसे मौकों पर बड़ी-बड़ी कंपनियां और मॉल ग्राहकों के लिए अपने-अपने उत्पादों पर बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर करती हैं। आमतौर पर कंपनियों द्वारा किए गए यह डिस्काउंट ऑफर ग्राहकों को लुभाने के लिए होते हैं। ग्राहक भी असमंजस (कंफ्यूज) में रहता है कौन सा उत्पाद लिया जाए और कौन सा न लिया जाए। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में चल रहा है। दिल्ली भी सोचती होगी कि मैं देश की राजधानी हूं और मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है लेकिन राजनीतिक दलों ने मेरे स्टैंडर्ड का भी ध्यान नहीं रखा। सही मायने में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से जनता के लिए लूट का ऑफर चल रहा है। दिल्ली वासी भी सोच रहे हैं जिस पार्टी का सबसे अच्छा ऑफर होगा वोट भी उसी को होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है की राजधानी में लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार में फ्री योजनाओं का लाभ लेने की आदत भी पड़ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वोटरों के लिए सबसे पहले 'फ्री की सौगात' बांटना शुरू किया था। करीब 10 साल पहले दिल्ली में आप की सरकार आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी वासियों के लिए मुफ्त बिजली और पानी समेत तमाम योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। केजरीवाल का मफ्त की रेवड़ियों का फार्मूला हिट रहा और पिछले तीन बार से लगातार दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है। इन दिनों राजधानी में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। चौथी बार दिल्ली को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार राजधानी की जनता के लिए कई बड़ी मुफ्त की घोषणाएं कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की राह पर

चल पड़ी हैं। दिल्ली की तीनों पार्टियां पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच लोकलुभावन चुनावी वादों की जैसे होड़ सी मची हुई है। सबसे पहले केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी को दी गई छूटों के आधार पर अपनी ब्रांडिंग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी उसकी राह पर चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीनों प्रमुख पार्टियों ने लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा और महिलाओं के लिए नकद लाभ शामिल हैं। तीनों ही दलों ने मुफ्त सुविधाएं देने का एलान किया है। इन दलों ने सीधे कैश देने की प्रथा को जारी रखा है। रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतना ऐसा फॉर्मूला बन चुका है, जिसे चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से आजमाता है, चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। यही कारण है कि कभी हिमाचल प्रदेश से तो कभी कर्नाटक से ऐसे समाचार मिलते रहते हैं, जिसमें मुफ्त योजनाओं से बढ़े आर्थिक बोझ के कारण सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पातीं। क्या दिल्ली भी उसी राह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा-आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुफ्त की घोषणाएं कर रही हैं, चुनाव के बाद उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के सामने दो ही विकल्प होंगे। या तो उसे आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसे अतिरिक्त आय हो और वह अपने वादे को पूरा कर सके, या उसे केंद्र या अन्य स्रोतों से उधार लेना पड़ेगा। अन्यथा वादों को पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी-

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सुनाई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। केंद्र के इस फैसले के बाद जल्दी ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट

दिल्ली चुनाव के लिए आप, भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया लोकलुभावन घोषणा पत्र

लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां एक बार फिर मुफ्त की स्कीमों पर जोर लगाया है तो इस बार भाजपा और कांग्रेस ने आगे निकलने की होड़ में मचा दी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार-बार साफ किया गया है कि दिल्ली में मुफ्त वाली स्कीमों को जारी रखा जाएगा। दिल्ली सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर जैसी योजनाएं चला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो वह महिलाओं को 2100 रुपये की मासिक मदद उपलब्ध कराएंगे। पहले उन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था। फिर चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये करने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का एलान किया है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। यह इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में उपलब्ध होगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी घोषणा की। पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18 हजार रुपये हर महीने सम्मान राशि के तौर पर दी जाएगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक दशक से भी ज्यादा वक्त से राजनीतिक वनवास काट रही है। वह भी वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसने भी प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा पढ़े-लिखे बेरोजगारों को एक साल की अप्रेंटिसशिप और इस दौरान उन्हें हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया है। केंद्र की आयुष्मान योजना या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुफ्त इलाज के वादे की काट करते हुए कांग्रेस ने 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। इसके अलावा मुफ्त राशन किट, 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलिंडर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का एलान किया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। वह अपनी खोई जमीन पाने के लिए कई चुनावी घोषणाएं की। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को 8500 रुपये हर महीने देने की बात कही। इसके साथ ही उन्हें एक साल की अप्रेंटिसशिप पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मकसद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार विधानसभा चुनाव में जारी किए गए संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये हर महीने देने का वादा किया है, साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21000 रुपए और 6 पौष्टिक आहार किट देने का भी वादा किया है। इसके अलावा गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, होली-दीवाली पर एक-एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है। बीजेपी ने दिल्ली के बुजुर्ग मतदाताओं को लुभाने पर भी खास ध्यान दिया है। बीजेपी ने 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर, 2500 रुपये करने का वादा किया है। वहीं, 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि की पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने की बात कही है। वही इसके अलावा 2500 रुपये महीना पेंशन देने का एलान किया गया है, साथ ही बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने की भी घोषणा पार्टी ने की है। हालांकि कांग्रेस ने बुजुर्गों के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। भाजपा ने कहा है कि फ्री बिजली और पानी की सुविधा जैसे दिल्ली में चल रही है, वो उसी तरह जारी रहेंगी। यानी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली उसी तरह से मिलती रहेगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए दिल्ली की बसों में जो मुफ्त सुविधा चल रही है, वो जारी रहेगी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र में कौन सा घोषणा पत्र सबसे बेहतर है, इसका फैसला तो जनता 8 फरवरी को सुनाएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं, 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है।

संकल्प पत्रों की बहार: चुनावी मौसम में रेवड़ियों की बहार के चलते भाजपा, कांग्रेस और आप ने फेस्टिव सीजन ऑफर की घोषणा की दी है। तीनों पार्टी के नेता अपने-अपने ऑफर प्रस्तुत करते हुए

बैठक में मोदी सरकार ने इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 1.20 करोड़ मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले की गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के एजेंडा में यह फैसला नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होना है, उससे काफी पहले ही नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, ताकि उसकी सिफारिशें वक्त पर मिल जाएं और उन्हें समय पर लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक साल पहले प्रक्रिया शुरू करने से आयोग को सिफारिशें देने और सरकार को उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होना है। इसी वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके संगठन 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में संशोधन किया जा सके और पेंशन भुगतान तय किया जा सके। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सातवां वेतनमान आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 में लागू किया था। इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 14% की बढ़ोतरी करना शामिल था। सातवां वेतनमान आयोग से पहले, चौथे, पांचवें और छठें वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का रहा था। उल्लेखनीय है कि बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए हर दस साल पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 में बना था और इससे सरकारी खजाने पर 40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में बना था जिससे सरकार पर 144 करोड़ का बोझ पड़ा था। इसके बाद चौथा वेतन आयोग जून 1983 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर 1,282 करोड़ का बोझ पड़ा था। पांचवां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना था। इससे सरकारी खजाने पर 17000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बनाया गया था और इससे सरकार को 40000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ा था। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था जिसकी सिफारिशें 2106 में लागू हुई थी। इससे सरकारी खजाने पर 114000 करोड़ को बोझ पड़ा था। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

> ‘23 जनवरी को होने वाले उत्तराखंड का चुनाव के लिए राजधानी देहरादून समय पहाड़ो तक प्रचार का शोर दिखाई दे रहा है। भाजपा की ओर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और गणेश गोंदियाल ने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैली कर रहे हैं। दोनों पार्टी रही हैं । महिला पार्षदों के प्रचार अभियान में भाजयुमो एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी युवतियां भी डोर-टू-डोर प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस महिला पार्षद प्रत्याशियों के लिए युवा कांग्रेस, एनएसयूआइ की महिला कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी टोलियां बनाकर वार्डों में प्रचार कर रही हैं।’

निकाय चुनाव के रंग में रंगा उत्तराखंड, भाजपा-कांग्रेस ने झोंकी ताकत

उत्तराखंड का चुनाव में केवल तीन दिन रह गए हैं। समूचा उत्तराखंड निकाय चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों तक चुनावी प्रचार जोरों पर है। गली-मोहल्लों में प्रचार का शोर दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। महिला पार्षदों के प्रचार अभियान में भाजयुमो एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी युवतियां भी डोर-टू-डोर प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस महिला पार्षद प्रत्याशियों के लिए युवा कांग्रेस, एनएसयूआइ की महिला कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी टोलियां बनाकर वार्डों में प्रचार कर रही हैं। भाजपा की ओर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। सीएम धामी हर रोज दो से तीन चुनावी रैली कर रहे हैं । मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी चुनाव मैदान में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रैली कर रहे हैं। इन चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की भी परीक्षा होने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और गणेश गोंदियाल अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैली कर रहे हैं। दोनों पार्टी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले टिहरी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में लोगों को बहला-फुसलाकर धर्मातरण का काम किया जा रहा था। इसी तरह राज्य के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार धर्मातरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई और दस साल तक की सजा का प्रावधान बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दंगा रोधी कानून बनाया। अब प्रदेश में कोई दंगा करके, मारपीट करेगा या फिर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी भरपाई उसी व्यक्ति से की जाएगी। बीजेपी सरकार ने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया, जिसका परिणाम ये हुआ है कि बीते तीन सालों में 19 हजार से ज्यादा युवाओं को निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी मिली। इस दौरान कोई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। कहीं पर कोई नकल नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा ने प्रदेश के 11 नगर निगमों में आने वाले 5 सालों के लिए विजन का संकल्प पत्र में शामिल

उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव चुनाव के चर्चित चेहरे

सौरभ थपलियाल

वीरेंद्र पोखरियाल

ललित जोशी

मोनिका महर

दिनेश चंद्र मास्टर जी

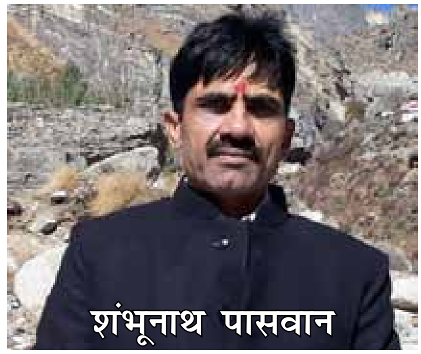
शंभूनाथ पासवान

किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास कार्य को आगे बढ़ा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। जिससे प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्य को तेजी से बढ़ाएगी। सीएम ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता सिर्फ घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि उन घोषणाओं को वास्तविकता में बदलना है। आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा यह संकल्प पत्र न केवल विकास योजनाओं का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भाजपा की कार्यशैली और पारदर्शिता को भी साबित करता है। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर नागरिक को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है। साथ ही मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। राज्य में युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सीएम धामी ने प्रदेश में इसी माह यूसीसी को लागू करने की बात कही है। निकाय चुनाव के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा, जो प्रदेश के नागरिकों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को भी लागू कर दिया जाएगा, जिससे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा रहा हैं। वहीं, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा को निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है। उन्होंने कहा जो घोषणा पत्र बीजेपी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा है, उसमें निकाय से संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की गई है। गरिमा दसौनी ने आरोप लगाते हुए कहा इस संकल्प पत्र में थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों को उठाया गया है। जिसका दूर-दूर तक आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा भाजपा की निकाय चुनाव में हालत पतली हो चुकी है, इसलिए भाजपा को साम, दाम, दंड ,भेद अपनाना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा भाजपा शासन काल में तमाम नगर निगमों की हालत खराब चल रही है। देहरादून नगर निगम अकेला ऐसा क्षेत्र है, जिसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र से भेजे गए, मगर चारों तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो आम जनता के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधा नहीं मिली है। दूसरी और कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के कई नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। करन माहरा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। लोग कांग्रेस को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं।जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए इसी महीने 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे।

मेयर संवाद कार्यक्रमः महापौर प्रत्याशियों ने देहरादून को सुदृढ़ बनाने का अपना-अपना रोडमैप प्रस्तुत किया

देहरादून सिटीजन्स फोरम ने किया आयोजन, सभी मेयर प्रत्याशियों को अपनी बात रखने के लिए मिले 12 मिनट

प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनावों का महासमर चल रहा है। प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में सत्ताधारी दल भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दल कांग्रेस, अन्य राजनैतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समर में अपनी ताकत झोंक रहे हैं।

प्रदेश की नगर निगम की सबसे हॉट सीट यानी राजधानी देहरादून का मेयर चुनाव सबसे रोचक बन गया है, जहां भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों के साथ-साथ कुल दस निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं।

इसी क्रम में, देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में देहरादून सिटीजन्स फोरम द्वारा 'देहरादून ग्रीन एजेंडा' थीम पर मेयर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न वर्गों से भारी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। मेयर संवाद में बोलने वाले प्रत्याशियों का चयन पर्ची लाटरी द्वारा किया गया। सभी प्रतिभागियों ने देहरादून के इस किस्म के पहले आयोजन की सराहना की। मेयर प्रत्याशियों को अपनी बात रखने के निर्धारित 12 मिनट का समय दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान सभी महापौर प्रत्याशियों ने अपने-अपने विज़न से सभी को अवगत कराया और यह बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य दून की हरियाली को बनाए रखना होगा। इसके अतिरिक्त, पार्किंग की व्यवस्था को प्राथमिकता देना और नालों में तब्दील हो चुकी नदियों को पुनः संवारना भी उनकी योजनाओं में शामिल है। सम्पूर्ण मेयर प्रत्याशी इन मूल मुद्दों पर देहरादून सिटीजन्स फोरम के दृष्टिकोण से सहमत नजर आए।

मेयर संवाद की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने की, जिन्होंने शहर में अगले पांच वर्षों में 10 लाख पेड़ लगाने की योजना प्रस्तुत की। इसके अलावा, उन्होंने पॉलिथीन की समस्या को कारखानों में ही स्रोत पर रोकने और चुनाव जीतने के बाद वार्डों में जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही।

दूसरे वक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र आनंद सिंह ने देहरादून में अगले पांच वर्षों में पांच लाख सीसीटीवी कैमरे और 10,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किन्नर समाज के हित में कार्य करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

पर्ची चयन के आधार पर अगला वक्तव्य उत्तराखंड क्रांति दल के कैप्टन बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने दिया, जिसमें उन्होंने इको टास्क फोर्स का गठन करने, पॉलिथीन की समस्या को शहर की सीमाओं में रोकने और इंदौर के कचरा प्रबंधन मॉडल से सीखने का वादा किया। साथ ही, उन्होंने एक मजबूत भू कानून की भी पैरवी की।

अंत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सौरभ थपलियाल ने अपनी पार्टी के संकल्प पत्र को दोहराते हुए सामुदायिक हॉल बनाने, साइकिल ट्रैक और वॉकिंग पाथ बनाने की बात की। संवाद के दौरान मलिन बस्तियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अगली सुनवाई, शहर में बढ़ते नशे और रिस्पना जैसी नदियों में पानी की गुणवत्ता के चिंताजनक सवालों को संवाद में पब्लिक ने अधिकांश उनसे सवाल दागे।

सभी महापौर प्रत्याशी अपने-अपने विज़न के साथ यह स्पष्ट करते हुए नजर आए कि दून की हरियाली को बनाए रखना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके साथ ही, पार्किंग की व्यवस्था को प्राथमिकता देना और नालों में तब्दील हो चुकी नदियों को फिर से संवारने का काम किया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत देहरादून सिटीजन्स फोरम के जगमोहन मेहंदीरत्ता और भारती जैन ने की, जबकि फोरम के ग्रीन एजेंडा पर जानकारी अनूप नौटियाल और फ्लोरेंस पांधी ने दी। मेयर संवाद की रूपरेखा को रितु चटर्जी और अनीश लाल ने साझा किया।

एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी विजय भट्टराई ने भी मेयर संवाद कार्यक्रम में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में देहरादून सिटीजन्स फोरम के सदस्य सुधीर वढेरा, आशीष गर्ग, कुसुम कोहली, आशा रानी कपूर, अनूप बड़ोला, नितिन शाह, रमन्ना, डॉक्टर विमल नौटियाल, लोकेश ओहरी, सुनील नेहरू, रणबीर चौधरी, अनिल जग्गी, अभिषेक भट्ट, राजीव ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता रवि चोपड़ा, निर्मला बिष्ट, जयदीप सकलानी, प्रदीप कुकरेती, और अन्य संस्थाओं और देहरादून सिटीजन्स फोरम के कई और सदस्य तथा शहर के नागरिक उपस्थित रहे।

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 47 साल बाद बदला अपना पता

कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में 24, अक्टूबर रोड के नाम से जाना जाता था। 15 जनवरी से कांग्रेस के मुख्यालय का पता अब बदल कर 9ए कोटला रोड हो गया। यह दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर है। पार्टी का नया मुख्यालय छह मंजिला है, जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से पुकारा जाएगा। 24, अकबर रोड कभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर हुआ करता था। इसके अलावा यह इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी रहा। उससे पहले यह बंगला बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। बंगले को यह नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था। इंदिरा भवन को लगभग 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह भवन पार्टी की विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता का प्रतीक भी है। पहली मंजिल पर हाईटेक ऑडिटोरियम है। इसके अलावा किसान प्रकोष्ठ, डेटा विभाग और कई विभागों के द"तर समेत कुल 18 कमरे हैं। द्वितीय तल पर 24 कमरे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी राजधानी दिल्ली में 47 साल बाद अपना पता बदल दिया। अभी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में 24, अक्टूबर रोड के नाम से जाना जाता था। 15 जनवरी से कांग्रेस के मुख्यालय का पता अब बदल कर 9ए कोटला रोड हो गया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने दिल्ली में नए पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी समय तमाम नेता भी मौजूद रहे। यह दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर है। पार्टी का नया मुख्यालय छह मंजिला है, जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से पुकारा जाएगा। 24, अकबर रोड कभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर हुआ करता था। इसके अलावा यह इंटेलिजेंस ब्यूरो की पॉलिटिकल सर्विलांस विंग का ऑफिस भी रहा। उससे पहले यह बंगला बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। बंगले को यह नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था। दरअसल, इसी बंगले में म्यांमार की भारत में राजदूत डॉ. खिन काई रहती थीं। वे म्यांमार की आयरन लेडी कही जाने वाली आंग सान सू की की मां थीं और करीब 15 साल तक आंग के साथ इस बंगले में रही थीं। 9ए, कोटला रोड, नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। यह प्रतिष्ठित इमारत कांग्रेस पार्टी के असाधारण अतीत को याद करते हुए उसकी दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया है। कांग्रेस के नए ऑफिस का मेन एंट्रेंस बदल सामने नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से है। इसकी वजह भाजपा है। दरअसल, ऑफिस का फ्रंट एंट्रेंस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। ऐसे में एड्रेस पर यह नाम आता, इसलिए पार्टी ने फ्रंट एंट्रेंस के बजाय बैकडोर एंट्री यानी पिछले दरवाजे से एंट्रेंस चुना, जो कोटला रोड पर खुलता है। कांग्रेस के नए मुख्यालय का काम पिछले कई वर्षों से जारी था। इंदिरा भवन को लगभग 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह भवन पार्टी की विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता का प्रतीक भी है। पहली मंजिल पर हाईटेक ऑडिटोरियम है। इसके अलावा किसान प्रकोष्ठ, डेटा विभाग और कई विभागों के दफ्तर समेत कुल 18 कमरे हैं। द्वितीय तल पर 24 कमरे हैं। इनमें राष्ट्रीय सचिव बैठेंगे। तीसरी मंजिल पर 18 कमरे हैं, जहां स्वतंत्र प्रभार वाले प्रभारी बैठेंगे। चौथी मंजिल पर संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत पार्टी के अन्य महासचिवों का दफ्तर होगा। इस तल पर 12 बड़े कमरे हैं। पांचवें फ्लोर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए तीन बड़े-बड़े दफ्तर बनाए गए हैं।

साल 1978 में कांग्रेस पार्टी 24 अक्टूबर

रोड में शिफ्ट हुई थी--
कांग्रेस के राजनीतिक दल बनने का सफर 28 दिसंबर 1885 में शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक पार्टी के कई मुख्यालय बदले हैं। सबसे पहले इलाहाबाद में 1931 में आनंद भवन को मुख्यालय बनाया गया, जिसे आजादी के बाद दिल्ली में 7 जंतर मंतर रोड पर शिफ्ट किया। 1971 में पार्टी का कार्यालय पांच राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हुआ। इसका एड्रेस 3, रायसीना रोड था। इसके ठीक सामने 6, रायसीना रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे, इसलिए कांग्रेस ने यहां भी बैकडोर एंट्री चुनी थी। 1978 में कांग्रेस में टूट के बाद ऑफिस पार्टी सांसद जी वेंकटस्वामी को अलॉट बंगले 24, अकबर रोड में शिफ्ट किया गया था। तब से अब तक यह कांग्रेस मुख्यालय का पता रहा। नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद भी कांग्रेस अपना पुराना ऑफिस खाली नहीं करेगी। यहां बड़े नेताओं का उठना-बैठना होता रहेगा। कांग्रेस से पहले भाजपा ने भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद भी अपना पुराना ऑफिस 11, अशोक रोड नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस जोन में भीड़-भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले भाजपा ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। कांग्रेस ने भी अपना नया ठिकाना भाजपा के पड़ोस में ढूंढा। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के विवादित बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा और आरएसएस को घेरते हुए 'इंडियन स्टेट' को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। राहुल ने कहा कि 'ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि यह सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन के खिलाफ है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई भारतीय राज्यों से भी है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा- मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ-साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। राहुल ने कहा कि भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते। उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। दरअसल, भागवत ने 13 जनवरी को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 'प्रतिष्ठा द्वादशी' के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस टिप्पणी से कांग्रेस का घिनौना सच' सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 'हम अब भाजपा, आरएसएस और 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज व्यवस्था) से लड़ रहे हैं'। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्यों से लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के भाषण की एक क्लिप शेयर की है। मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी ने अब भारतीय राज्यों के खिलाफ ही खुली जंग का एलान कर दिया है। यह सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से लिया गया है।

दिल्ली में शुरू हुआ कारों का मेला, कंपनियों ने दिखाई भविष्य की गाड़ियों की झलक

'हर साल आयोजित होने वाला ऑटो एक्सपो राजधानी दिल्ली में 18 जनवरी से शुरू हो गया है। 22 जनवरी तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में हुंडई क्रेटा ईवी, मारुति सुजुकी ई-विटारा, एमजी साइबरस्टर समेत दुनियाभर की कारें लॉन्च होने जा रही हैं। विनफास्ट जैसी कंपनी भारत आ रही है। साथ ही महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, किआ समेत लग्जरी कार कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही हैं। मोटरसाइकल, स्कूटर, कंपोनेंट्स, हैवी मशीनरी, टायर्स के साथ ही दुनियाभर के नए प्रोडक्ट्स और टेक्नॉलजी को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। मारुति ने अपनी पहले इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का रिवील (पेश) किया है। इस बार भारत मंडपम के साथ-साथ द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चलेगा।'

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार 18 जनवरी से पांच दिवसीय कार मेला की शुरुआत हुई। देश-विदेश की बड़ी वाहन कंपनियां राजधानी दिल्ली में एक से बढ़कर एक हाईटेक गाड़ियों की झलक दिखाने उतरी हैं। हर साल आयोजित होने वाला ऑटो एक्सपो राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है। 22 जनवरी तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में हुंडई क्रेटा ईवी, मारुति सुजुकी ई-विटारा, एमजी साइबरस्टर समेत दुनियाभर की कारें लॉन्च होने जा रही हैं। विनफास्ट जैसी कंपनी भारत आ रही है।

इस बार एक्सपो का ऑफिशियल नाम 'द मोटर शो' रखा गया

इस बार एक्सपो का ऑफिशियल नाम 'द मोटर शो' है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में फ्यूचर मोबिलिटी की झलक मिलेगी। इसमें ऑटो के साथ-साथ टेक कंपनियां भी शामिल हो रही है। इसमें ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। जानकारी के अनुसार, यह एक्सपो 17-22 जनवरी 2025 को तीन अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। जिसमें नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि तथा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में। एक्सपो में नौ से ज्यादा एक ही समय में होने वाले कार्यक्रमों, 20 से ज्यादा सम्मेलनों और पवेलियन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, एक्सपो में मोबिलिटी क्षेत्र में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि उद्योग और क्षेत्रीय स्तरों के बीच सहयोग को सक्षम बनाया जा सके। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार, एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सडीज, बीएमडब्ल्यू बीवाईडी समेत कई बड़े ब्रांड अपने नए मॉडल शोकेज करेंगे। यह भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है। इवेंट में इस बार कंपनियों का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेश करने पर है। इसमें मारुति सुजुकी की ई-विटारा, हुंडई क्रेटा ईवी, एमजी की साइबस्टर और एम9, किआ की ईवी 6 फेसलिफ्ट और सिरोस, स्कोडा की एन्याक और एलरोक टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी और सिएरा ईवी पेश की जाएंगी। इसके अलावा भारत में पहली सोलर कार ईवा और सरला एविएशन की फ्लाइंग टैक्सी भी पेश की जाएगी। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऑटो एक्सपो में हिस्सा लेने वाली मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इनमें टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, हुंडई मोटर इंडिया, किआ इंडिया और स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, पोर्श इंडिया और बीवाईडी जैसे ग्लोबल लक्जरी ब्रांड इसमें शामिल होंगे। टू-व्हीलर सेक्शन में टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल और यामाहा इंडिया जैसे मार्केट लीडर ब्रांड भाग लेंगे। वहीं, कमर्शियल सेक्शन में वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लीलैंड, जेबीएम और कमिंस इंडिया जैसे नाम शामिल होंगे। इसके अलावा, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, टीआई क्लीन मोबिलिटी, ईका मोबिलिटी और वियतनाम स्थित विनफास्ट जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी अपने मॉडल और टेक्नोलॉजी शोकेज करेंगी।

साथ ही महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, किआ समेत लग्जरी कार कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही हैं। मोटरसाइकल, स्कूटर, कंपोनेंट्स, हैवी मशीनरी, टायर्स के साथ ही दुनियाभर के नए प्रोडक्ट्स और टेक्नॉलजी को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इस मेगा इवेंट का शुक्रवार को उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करें को जब भारत विश्व की सबसे बड़ी तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा तब भारत का ऑटो मार्केट कहां होगा। कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी और चौड़ी सड़कों का अभाव था। पिछले साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। इस इवेंट में देश-विदेश की ऑटो कंपनियां शामिल हो रही हैं। मारुति ने अपनी पहले इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का रिवील (पेश) किया है। कंपनी के अनुसार ये कार खुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। हुंडई अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूबी क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेगी। हुंडई ने क्रेटा ईवी को नई पहचान देने के लिए इसके डिजाइन में काफी बदलाव किए हैं। टाटा मोटर्स इस साल मोबिलिटी एक्सपो में अपनी आगामी कारों की शानदार झलक दिखाने वाली है, जिनमें हैरियर ईवी और सिएरा ईवी प्रमुख होंगी। टाटा की हालिया लॉन्च टियागो और टिगोर फेसलिफ्ट को भी टाटा मोटर्स पवेलियन में दिखाया जाएगा। बाद बाकी कर्व, कर्व ईवी, नेक्सॉन आईसीएनजी के साथ ही पंच फेसलिफ्ट भी दिख सकती है। किआ इंडिया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवी 6 का फेसलिफ्ट मॉडल शोकेस करने वाली है, जिसमें बेहतर रेंज और फीचर्स देखने को मिलेंगे। किआ कैरेन्स फेसलिफ्ट भी आ सकती है। साथ ही हालिया लॉन्च सिरॉस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस साल भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछली बार 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने शामिल हुए थे और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ-साथ द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक मिशन निदेशक स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में हुई संपन्न

स्वाति एस. भदौरिया, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) उत्तराखंड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मिशन निदेशक द्वारा एन.एच.एम. के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व अभियानों की समीक्षा की गई।

मिशन निदेशक द्वारा सीपीएचसी एवं गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों में स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी जा रही मूलभूत सेवाओं को बेहतर बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारयों को समय-समय पर मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

स्वाति एस. भदौरिया, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. द्वारा गंभीर एनीमिया के मामले पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने एनीमिया कैंपेन के सफतापूर्ण आयोजन हेतु जनपदों को निर्देशित किया।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 100 दिवसीय टीबी अभियान की समीक्षा करते हुए मिशन निदेशक द्वारा समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि अभियान के माध्यम से अत्यधिक लोगों की एक्स-रे मशीन के माध्यम से स्क्रीनिंग करते हुए टीबी मरीजों को चिन्हित किया जाए और समस्त डेटा को निक्षय पोर्टल पर ससमय अंकित किया जाए।

मिशन निदेशक द्वारा प्रदेश में आशाओं के लिए संचालित मोबाइल एकेडमी प्रशिक्षण कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों जिनमें चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर व टिहरी को पुरुस्कृत किया।

उन्होंने कम्युनिटी प्रोसेस के अंतर्गत रिक्त पदों जिनमें आशा, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक समन्वयक तथा जिला समन्वयक को आदर्श आचार संहिता के पश्चात् भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. मनु जैन, निदेशक, एन.एच.एम. द्वारा आशा सम्मेलन तथा जनसंवाद माह फरवरी तक पूर्ण करने हेतु जनपदों को निर्देशित किया।

बैठक में जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित डॉ. अजय नगरकर, डॉ. फरीदुजफर, डॉ. कुलदीप मार्तोलिया, डॉ. अर्चना ओझा, डॉ. उमा रावत, डॉ. आदित्य, डॉ. आकांशा सहायक निदेशक एन.एच.एम., डॉ. महेंद्र कुमार मौर्य, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा प्रतीभाग किया गया।

उत्तराखंड के सबसे बड़े संगठन देवभूमि पत्रकार यूनियन, पंजी. का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न

अनिल वर्मा अध्यक्ष व डॉ. वी.डी. शर्मा महासचिव निर्वाचित एवं कुंवर राज अस्थाना वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित

स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित देवभूमि पत्रकार यूनियन (पंजी.) उत्तराखण्ड के द्विवार्षिक चुनाव 2025-2026 में वरिष्ठ पत्रकार अनिल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष एवं डॉ. वी. डी. शर्मा प्रदेश महासचिव निर्वाचित घोषित किया गया।

उक्त घोषणा करते हुए चुनाव अधिकारी डॉ.चंद्र सिंह तोमर 'मयंक' एवं अशोक खन्ना ने संयुक्त रूप से बताया कि इनके अतिरिक्त सुभाष चंद्र जोशी व कुँवर राज अस्थाना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शशिकांत मिश्रा कोषाध्यक्ष, सिद्धनाथ उपाध्याय व महेंद्र सिंह नेगी सचिव, श्रीमती सरोजनी सेमवाल व दीपक धीमान संगठन सचिव, श्रीमती प्रेमलता भरतरी व राजेश भटनागर प्रचार सचिव निर्वाचित हुए।

इनके अतिरिक्त सर्वश्री विजय जायसवाल, भुवन उपाध्याय, संजीव शर्मा, तेजराम सेमवाल, हरेंद्र प्रसाद, राजेश शर्मा, अमित सहगल, डॉ. जमशेद उस्मानी, संजय गर्ग, अशोक कुमार पांडे सदस्य कार्यकारिणी चुने गए।

चुनाव से पहले पूर्व अध्यक्ष विजय जायसवाल द्वारा अध्यक्षीय आभार, पूर्व कोषाध्यक्ष सिद्धनाथ उपाध्याय द्वारा आयकृव्यय ओडिट रिपोर्ट एवं महासचिव डॉ. वी.डी. शर्मा द्वारा द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने पर दोनों चुनाव अधिकारीगण का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उपस्थित सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया गया। आम सभा व चुनाव प्रक्रिया में पूरे प्रदेश से भारी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।

काश! मैं उत्तराखंड में खेल पाती नेशनल गेम: चित्रांशी रावत

चक दे इंडिया फेम चित्रांशी रावत ने कहा-अब और निखरेंगे पहाड़ के खिलाड़ी

राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से खुश, सरकार को दी बधाई

चित्रांशी रावत यानी चक दे इंडिया फिल्म की कोमल चौटाला। कई वर्षों बाद भी चित्रांशी रावत की सबसे मजबूत पहचान ये ही किरदार है। हॉकी खिलाड़ी होने की वजह से ही चित्रांशी को यह किरदार मिला और इसी वजह से वह इस किरदार को जीवंत कर पाई। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के माहौल के बीच चित्रांशी का खिलाड़ी मन दूर मुंबई में भी मचल रहा है। चित्रांशी का यही कहना है-काश मेरे स्कूल-कॉलेज के दिनों में उत्तराखंड में नेशनल गेम होते। काश! मैं उत्तराखंड में नेशनल गेम खेल पाती।

चित्रांशी रावत 12 वीं क्लास तक हॉकी खेलती रहीं। वह हॉकी की शानदार खिलाड़ी रहीं हैं। इस दौरान जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल समेत कई राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता में उन्होंने शिरकत की। सब जानते हैं कि हॉकी पर केंद्रित ब्लॉकबस्टर फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला के किरदार के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी, जो हॉकी खिलाड़ी हो। चित्रांशी ने इस भूमिका को किस कदर शानदार ढंग से निभाया, ये भी हम सब जानते हैं।

चित्रांशी फिल्मों में व्यस्त हैं, लेकिन उत्तराखंड में 38 वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट है। फोन पर बातचीत में चित्रांशी ने कहा-एक खिलाड़ी होने के नाते मैं यह जानकर रोमांचित हूं कि मेरे गृह राज्य उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। मैं जानती हूं कि इस आयोजन की कितनी अहमियत है। उत्तराखंड सरकार को बधाई। चित्रांशी कहती है-स्कूल कॉलेजों के जमाने में मै नेशनल लेवल पर खेलने के लिए कभी दिल्ली, कभी जबलपुर, कभी कपूरथला जाया करती थी। काश उस वक्त उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होते, तो मैं अपनी धरती पर हॉकी खेलती।

फिल्म अभिनेत्री व पूर्व हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी का कहना है-हमारे खिलाड़ी पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब और निखरकर सामने आएंगे। राष्ट्रीय खेलों से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा-पहाड़ के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेलों का यह प्लेटफार्म बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे।

उत्तराखंड की हॉकी टीम बढ़िया करेगी -यूं तो चित्रांशी को उम्मीद है कि ज्यादातर खेलों में उत्तराखंड की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन उनकी उम्मीद हॉकी से बहुत ज्यादा है। चित्रांशी कहती हैं-हॉकी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वंदना कटारिया भारतीय हॉकी टीम में खेल रही है। यह बड़ी बात है। चित्रांशी के अनुसार-जब वह हॉकी खेला करती थीं, तब वंदना और उनकी बहन उन्हें कैंपों में मिला करती थी। दोनों अच्छी खिलाड़ी रही हैं।

राष्ट्रीय स्तरीय मैराथन 'रेड रन' प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड का गौरवपूर्ण प्रदर्शन

18 जनवरी, 2025 को नाको (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) भारत सरकार द्वारा एचआईवी/एड्स के नियंत्रण एवं जागरूकता विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय मैराथन 'रेड रन' का आयोजन गोवा के पंजिम में किया गया। इस मैराथन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसोनाइक (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा किया गया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश के 26 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा पूर्व में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड की सुश्री अंजली ने 10 किमी मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखण्ड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें 35,000/- की नगद धनराशि का पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसोनाइक द्वारा प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय स्तरीय 'रेड रन' प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति से श्री धर्मेन्द्र रावत (उपनिदेशक, वित्त), श्री अनिल सती (आईईसी), श्री संजय सिंह बिष्ट (उपनिदेशक, टीआई), श्री अजय सुन्द्रियाल (अनुभाग सहायक), तथा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून से श्री कंवल जीत सिंह कलसी (पुरुष गाइड एवं प्रशिक्षक) और श्रीमती रविन्द्र कौर (महिला गाइड एवं प्रशिक्षक) ने प्रतिभाग किया।

उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के मध्य संपादित हुआ भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन

मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन

उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसलटिंग इंजिनियर्स के मध्य सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत डॉ. बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन की गरिमामय उपस्थिति में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में समझौता संपन्न हुआ। वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समझौता ज्ञापन को उत्तराखंड के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में एक माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा के इस एमओयू के माध्यम से न केवल स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित रहते हुए समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रण ी देश है और इनके तकनीकी सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इसकी अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है। कहा कि राज्य में भूतापीय ऊर्जा के व्यवहारिकता के अध्ययन का व्यय भार का वहन आइसलैंड सरकार द्वारा किया जाएगा। संदर्भित है कि

- **उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास में जुड़ेगा नया आयाम**
- **आइसलैंड की कंपनी वर्किस की विशेषज्ञता का लाभ**
- **उत्तराखंड के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में माइलस्टोन होगा साबित**
- **उत्तराखंड में भू तापीय ऊर्जा के दोहन योग्य 40 भूतापीय स्थल चिन्हित**
- **भारत के 2070 के कार्बन न्यूट्रल बनने के संकल्प में होगा सहायक**

भविष्य की सोच के साथ विकास

इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने को सोच एनडी तिवारी की थी जिसको धरातल पर बीपी पाण्डेय और रामचंद्रन जैसे IAS अधिकारियों ने उतारा। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के वाक्यांश 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये सपना पूरा करने का बीड़ा युवा और ऊर्जावान नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया है, जिसको धरातल पर डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम जैसे विकासवादी सोच और दूरदर्शी IAS अधिकारी कर रहे हैं। दूरदर्शिता का नमूना: 2013-14 में मीनाक्षी सुंदरम जी ने एमडीडीए के वीसी के रूप में घंटाघर से गांधी पार्क तक बिजली की लाइन अंडरग्राउंड करवाई थी। ये एक सफल विकासवादी प्रयोग था। आज जब मीनाक्षी जी सचिव ऊर्जा हैं तो उन्होंने पूरे देहरादून में बिजली की लाइनों को भूमिगत करवाने का काम शुरू करवा दिया। पैसा भी एडीबी से ले आए। यूपीसीएल को बिजली चोरी से होने वाला नुकसान भी जीरो हो जाएगा। शहर की तारों के जंजाल से भी मुक्ति मिलेगी। भू तापीय ऊर्जा को लेकर जो पहल मीनाक्षी सुंदरम ने की है। इसका लाभ 10 वर्ष बाद जिस पीढ़ी को मिलेगा उनके लिए वो वरदान से कम नहीं होगा।

भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं वाडिया हिमालय भू- विज्ञान संस्थान देहरादून के द्व ारा किए गए आकलन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 भू- तापीय स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। मै. वर्किस कंसलटिंग इंजिनियर्स आइसलैंड की प्रमुख कंपनी है जो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता रखती है। उनकी तकनीकी क्षमताएं और अनुभव उत्तराखंड में भूतापीय परियोजनाओं को तेजी से और कुशलता से विकसित करने में सहायक होंगे। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर व दीपेंद्र चौधरी, विशेष सचिव/रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, प्रबंध निदेशक यू.जे.वी.एन. लिमिटेड संदीप सिंहल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी सहित वर्किस कंपनी से हैंकर हैरोल्डसन, रंजीत कुंना व आइसलैंड एंबेसी से राहुल चांगथम उपस्थित थे।

निजी बसों की सवारियों को भी मिलेगी दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा

वाहन दुर्घटना के उपरांत मिलेगी एकसमान राहत राशिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है। अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही, सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स व फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के बीच हुआ एम.ओ.यू.

ई-कॉमर्स व्यवसायी एवं हितधारकों को अधिक सुलभ और समावेशी तकनीकी उपलब्ध कराई जाएगीः राजेश्वर पैन्यूली

15 जनवरी, 2025 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) व फेडरेशन अक्क अक्ल इंडिया व्यापार मंडल के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर हुवे। फेडरेशन के महासचिव आर के गौर व ONDC की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री टी कोशी (T Koshy-MD-CEO -ONDC) ने फैम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयेन्द्र तन्ना जी की ओर अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किये।

फेडरेशन की ओर से ट्रस्टी श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने इस बारे में बातचीत करते हुवे बताया की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ई-कॉमर्स को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। यह नेटवर्क ई-कॉमर्स के माध्यमसे सभी व्यवसायी को ओर हितधारकों को अधिक सुलभ और समावेशी तकनीकी एकदम व्यजबी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस एम ओ यू के साथ ही ONDC के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे के उपयोग के साथ सभी उपभोक्ताओं को अपने विक्रेताओं के साथ बातचीत करने की अनुमति मिलेगी चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हो द्य यह सरकार द्वारा निर्मित ई-कॉमर्स के लिए भारत में बना सबसे सस्ता व सुरक्षित ई-प्लेटफॉर्म है, जो छोटे, मध्यम और सूक्ष्म व्यापारियों और व्यावसायिक इकाई के लिए बहुत उपयुक्त साबित होने वाला है। अब MOU होने के साथ ही फेडरेशन सभी सदस्य व्यापारियों को इस नई तकनीक का उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने का प्रबंध करेगा। फेडरेशन की ओर से आशा की गई इसके अधिकतम सुरक्षित उपयोग की क्षमता को देखते हुवे कहा जा सकता है की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) फैम के 18 राज्यों से लगभग 20 लाख से अधिक सक्रिय व्यापारियों की आवश्यकता को सम्बोधन कर सकने की क्षमता के कारण भविष्य में यह फ्लिपकार्ड ऐमेज़ॉन, जोमैटो आदि प्लेटफार्म से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा।

फेडरेशन के महासचिव आर के गौर व ONDC की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री टी कोशी एमडी एवं सी. ई. ओ. (T Koshy-MD-CEO -ONDC) ने MOU हस्ताक्षर किये। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जयेंद्र तन्ना जी ने सभी अपने सदेश में बधाई दी। इस अवसर पर महासचिव आर के गौर व राष्ट्रीय प्रवक्ता एवम् कोषाध्यक्ष (फैम) से चार्टेड एकाउटेंन्ट राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली सहित फैम के ONDC के समन्वयक एवम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय सदस्य श्री सतीश चौहान, फैम के राष्ट्रीय सचिव और उत्तरप्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह जी, उपाध्यक्ष उत्तरप्रदेश श्री अजय कुमार अग्रवाल, श्री रासबिहारी अग्रवाल (मथुरा) अध्यक्ष जिला हाथरस के श्री सुरेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। सरकार प्रेरित ONDC प्रकल्प का विस्तार अब बड़ी तेजीसे होगा इस विश्वास MD श्री कोशी ने व्यक्त किया और फैम को बधाई के साथ स्वागत किया।

पूर्व सैनिक अपने अनुभवों से समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करें- राज्यपाल

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पदक विजेता सैनिकों और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस (वेटरन्स डे) के अवसर पर राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ''एक शाम सैनिकों के नाम'' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों को राज्यपाल प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। (सूची संलग्न) कार्यक्रम में कुमांऊ स्कॉउट्स, 4वीं बटालियन असम रेजिमेंट और 14वीं राजपूताना राइफल्स को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का अनुभव और उनकी नेतृत्व क्षमता राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति उनका जीवन अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों से समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करें। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में वे अपना योगदान दें।

राज्यपाल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आएं और समाज और राष्ट्र को प्रेरित करने का काम करें। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने वीर शहीदों के परिजनों की देखभाल और उनकी हर परिस्थिति में सहयोग करते हुए उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं, ईसीएचएस लाभ और अन्य आवश्यक सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, जिसे 'देवभूमि' के साथ-साथ 'वीरभूमि' भी कहा जाता है। यहां अनेक वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है। यह हमारे सैनिकों और उनके परिवारों को संदेश देता है कि उनका बलिदान न केवल हमारे लिए अमूल्य है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते जब भी वे सैनिकों से जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होते है तो उन्हें लगता है कि वे अपने परिवार के मध्य है उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) जी की प्रेरणा से राजभवन में पहली बार आयोजित इस आयोजन को प्रेरणादायी बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखण्ड के हमारे वीर सैनिकों का योगदान अतुलनीय रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि ना केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता का भी प्रदर्शन कर सकती है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्य में अब तक करीब 1834 सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और ये संख्या हर वर्ष निरंतर बढ़ती

जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान हेतु निरंतर कार्य करते रहे हैं। देश में वन रैंक-वन पेंशन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ही की। जिससे पूर्व सैनिकों को ना सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हुई। एक सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने भी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा और समझा है। इसीलिए राज्य सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि शहीदों और उनके परिवारों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तराखंड में वीर बलिदानियों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है यह राज्य के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और सर्मपण का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष में 2025 के प्रथम माह में राज्य में समान नागरिक सहिंता लागू कर दी जायेगी इसके साथ ही इसी माह 28 जनवरी से राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जायेगा। जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगें, उन्होंने कहा कि इस आयोजन में देशभर के लगभग 10 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से इस आयोजन में आने वाले खिलाड़ियों एवं इससे जुड़े लोगों का हृदय से स्वागत करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश में आयोजित हुए जी-20 सम्मेलन में शामिल होने वाले महानुभावों को मिले सम्मान एवं आत्मीयता से देशभर में राज्य की समृद्ध परंपराओं को पहचान मिली है, हमारी अतिथि देवो भवः की परंपरा को आगे बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने भी अपने विचार रखते हुए सैन्य कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, आईजी आईटीबीपी संजय गुज्यांल, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल सहित बड़ी संख्या में सेवारत और भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे।

सम्मानित होने वाले सेवारत और भूतपूर्व सैनिक

मेजर गोविंद सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल शशि भूषण, कोमोडोर हनिश सिंह कार्की, कर्नल पीयूष भट्ट, कर्नल ऐश्वर्या जोशी, मेजर शिवम गुप्ता, मेजर प्रतीक बिष्ट, कैप्टन अक्षत उपाध्याय, मेजर सौरभ थापा, मेजर मनिक सती, मेजर प्रकाश भट्ट, मेजर रोहित जोशी, नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद, नायब सूबेदार पंकज सिंह झिंकवाण, हवलदार गोविंद सिंह, नायक ललित मोहन सिंह, नायक दीपक सिंह, नायब सूबेदार पवन सावंत, पूर्व सैनिकों में नायक विनोद कुमार और लांस नायक राजेश सेमवाल के अलावा सैनिक कल्याण विभाग के सूबेदार मेजर मोहन लाल भट्ट व हेमचन्द चौबे।

सम्मानित होने वाले अर्धसैनिक बल के जवान और अधिकारी

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के हेड कांस्टेबल कपिल देव और सिपाही (महिला) अहोंगशागबाम नानाओ देवी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के उपनिरीक्षक नवज्योति मनराल, मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार सिंह व आरक्षी राउत योगिन्द्र रामचन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के निरीक्षक बिरेन्द्र सिंह और हवलदार (महिला) अनिता राणा।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

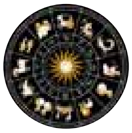

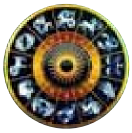

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी मिलेगी। आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। ज्यादा गुस्सा करने से बचें। दूसरों की छोटी-छोटी गलतियों को माफ करते चलें। अपने भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल है। परिवार और जीवन साथी का आपके लिए सहयोग बना रहेगा। भाग्यशाली अंक– 9

वृषभ राशि– विद्यार्थियों ने किसी प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। परिवार के साथ आपसी मतभेद को शांति से सुलझाएंगे। अपने आक्रामक स्वभाव पर काबू रखना अति आवश्यक है। बिजनेस में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। धन संबंधी मामलों में समझौता न करें। जोखिम भरे कामों से दूर रहें।

मिथुन राशि– आपको नए अनुभव मिल सकते हैं। उन्हें अपनाने से आपको सफलता मिल सकती है। रिश्तेदार या बाहरी लोगों के साथ मुलाकात में अपने व्यवहार में सौम्यता और शालीनता रखें। व्यस्तता और थकान के बावजूद थोड़ा समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है। बुखार और खांसी-जुकाम जैसी समस्या से राहत पाने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करें।

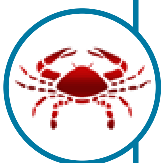

कर्क राशि– विद्यार्थियों को पढ़ाई और करियर संबंधी बेहतर जानकारियां मिलेंगी, जो फायदेमंद होंगी। गुस्से के कारण बिना वजह किसी से नोकझोंक या विवाद हो सकते हैं। इस समय इनकम के हिसाब से खर्चे ज्यादा रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी बनी रहेंगी। अपने व्यवहार और दिनचर्या के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न करें। भाग्यशाली अंक– 8

सिंह राशि– कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन करना सफलता देगा। मनन-चिंतन करने से अपनी ही उलझी हुई समस्याओं का समाधान मिलेगा। स्वार्थी दोस्तों से दूरी रखें। उनकी गलत सलाह आपको लक्ष्य से भटका सकती हैं। पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। वित्तीय मामलों में सुधार होगा। भाग्यशाली अंक– 1

कन्या राशि– युवाओं को करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर सावधान रहेंगे। अपनी बनाई नीतियों पर ध्यान देंगे। गैर जरूरी खर्चों पर भी कंट्रोल करें। घर में व्यवस्थित और सुखद माहौल रहेगा। मानसिक तनाव से थकान होगी और ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिटेशन में समय दें। भाग्यशाली अंक– 7

तुला राशि– थोड़ा समय खुद के लिए निकलना और घूमना-फिरना आपको दोबारा ऊर्जावान बनाएगा। कोई ईश्वरीय शक्ति की कृपा आपको महसूस होगी। लंबे समय से सोचा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में महत्वपूर्ण योजना पर काम करने का ऑफर मिल सकता है। इस समय छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। भाग्यशाली अंक– 9

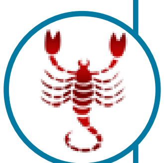

वृश्चिक राशि– किसी भी काम को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार कर लें। कोई भी फैसला लेते समय गंभीरता रखें, वरना पछताना पड़ सकता है। सरकारी नौकरीपेशा लोग पब्लिक प्लेस पर किसी लापरवाही से मुसीबत में फंस सकते हैं। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम करना आपकी सेहत को प्रभावित करेगा। भाग्यशाली अंक– 7

धनु राशि– इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों को कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में काम ज्यादा होने से एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। मेडिटेशन जरूर करें। घर का माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा। भाग्यशाली अंक– 9

मकर राशि– धैर्य और संयम से दिनचर्या को व्यवस्थित करते जाएं। अपनी प्रतिभा और काबिलियत को साबित करने का मौका मिलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। बिजनेस में सुधार करने के लिए कामकाज में बदलाव करना होगा। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखें। भाग्यशाली अंक– 2

कुंभ राशि– अपनी किसी कमजोरी पर जीत पाने के लिए की गई कोशिशों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आपकी लापरवाही से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पति-पत्नी आपसी तालमेल और सूझबूझ से घर की व्यवस्था को बेहतर बनाकर रखेंगे। भाग्यशाली अंक– 2

मीन राशि– फाइनेंस संबंधित कामों में आपकी कोशिशों के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। किसी अनुभवी और धार्मिक व्यक्ति के साथ समय बीताने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक बदलाव होगा। जीवनसाथी और परिवार वालों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। घर में किसी बच्चे के जन्म की खबर से खुशी मिल सकती है। भाग्यशाली अंक– 1

क्यों भारत में रिलीज नहीं हो रही फिल्म पंजाब 95?

दिलजीत दोसांझ पिछले कुछ वक्त से अपनी नई फिल्म पंजाब 95 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है। CBFC ने भी फिल्म में कई जगह कट्स लगा दिए हैं। इस बीच सिंगर और एक्टर ने मूवी को वर्ल्डवाइड रिलीज करने का फैसला ले लिया और ट्रेलर के साथ रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है।

पंजाब के फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ जो अब बॉलीवुड में भी बड़ा नाम काम चुके हैं। अपनी नई फिल्म के साथ थिएटर में पहुंचने को तैयार हैं। अमर सिंह चमकीला के बाद सिंगर और एक्टर अब पंजाब के मशहूर एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की बायोपि लेकर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फ़िल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए इस पर नया अपडेट शेयर किया है मगर इसमें एक ट्विस्ट भी है।

दिलजीत दोसांझ ने उठाया रिलीज डेट से पर्दा

दिलजीत ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में फिल्म के नए ट्रलेर को शेयर किया है। इस पोस्ट की खास बात ये रही कि अभिनेता ने मूवी की रिलीज डेट के बारे बता दिया है जोकि 7 फरवरी है। मगर इस मूवी को भारत में नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड रिलीज किया जाएगा इंडिया में फिलहाल के लिए इसे रिलीज नहीं किया जा रहा हैं क्योंकि मेकर्स और CBFC के बीच कई सीन को लेकर अभी विवाद चल रहा है। इसलिए मेकर्स ने फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में उतारने का फैसला लिया है।

भारत में क्यों रिलीज नहीं हो रही फिल्म?

इसके साथ ही बता दें, इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोडड्स और हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म तैयार होकर जब CBFC के पास पहुंची, तो बोर्ड ने उसमें 85 से लेकर 120 कट लगाने के आदेश दे डाले जिसके बाद से ही मेकर्स और बोर्ड के बीच कई तरह के क्लैश हो रहे हैं। एक खास बात और है इस फिल्म की, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानाकारी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखने के बाद टीम ने खालरा के परिवार से इसे अप्रूव कराया था।

कौन थे जसवंत सिंह खालरा?

दिलजीत दोसांझ फिल्म में जसवन्त सिंह खालरा की भूमिका निभाने वाले हैं। जसवंत सिंह खालरा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पंजाब में विद्रोह के दौरान हजारों सिख युवाओं की कथित न्यायेतर हत्याओं का पर्दाफाश किया था। खालरा साल 1995 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और आखिरी बार उन्हें अमृतसर में देखा गया था। इस घटना से हड़कंप मच गया था। बाद में जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर ने हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करवाया था।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629   Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

धन्यवाद उत्तराखंड

सफल प्रकाशन का गौरवशाली 14वाँ वर्ष

उत्तराखंड से प्रकाशित एकमात्र समाचार साप्ताहिक पत्रिका

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

मूल्यः रु 15/- मात्र

नए कलेवर में प्रत्येक रविवार

प्रत्येक रविवार

दिव्य हिमगिरि

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार
स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com